www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

SB NEWS

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 आंदोलन, हिंसा, तख्ता पलट और...
3 जिला कष्ट निवारण समीति की बैठक में सख्त नजर...
4 'कॉकटेल 2' के बाद रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का...

वर्ष: 10 | अंक: 112 | दिल्ली, शनिवार, 14 फरवरी 2026 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

हंगामेदार रहा बजट सत्र का पहला चरण, 9 मार्च तक कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली (एजेन्सी)। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के संस्मरण से जुड़े विवाद को लेकर कई दिनों तक चले तीखे राजनीतिक वाद-विवाद के बाद शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। यह विवाद संसद के बाहर भी चर्चा का विषय बना रहा। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका दोनों सदन अब तीन सप्ताह के अवकाश पर चले गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 9 मार्च को फिर से शुरू होगी। बजट सत्र, जो 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संसद को दिए गए संयुक्त संबोधन के साथ शुरू हुआ था, 65 दिनों में 30 बैठकों के साथ समाप्त होगा। मध्यावधि अवकाश के दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान अनुरोधों की जांच करेंगी। लोकसभा में दो फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव और इसका समर्थन करने के लिए भाजपा के दो सदस्यों के भाषण के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण चर्चा नहीं हुई और न ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस पर जवाब हो सका।

बेंगलुरु के पास आपस में टकराए कई वाहन, 7 लोगों की दर्दनाक मौत

कर्नाटक (एजेन्सी)। कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। होसकोटे के बाहरी इलाके में कई वाहनों की आपस में भिड़ंत होने से कम से कम सात लोगों की जान चली गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह दुर्घटना होसकोटे-डबासपेट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एम. सत्यवारा गांव के पास हुई। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे के बाहरी इलाके में कई गाड़ियों के टकराने से कम से कम सात लोगों की जान चली गई। यह घटना होसकोटे डबासपेटे नेशनल हाईवे पर एम सत्यवारा गांव के पास हुई। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल, एक कार और एक कैंटर ट्रक शामिल थे। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होसकोटे से देवनहल्ली जा रही थी।

प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 व 2 का किया उद्घाटन

लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का निर्माण किया गया है: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया।

संजना भारती/पीआईबी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 एवं 2 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी एक नए इतिहास के निर्माण के साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि विक्रम संवत 2082, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी, 24 माघ, शक संवत 1947, जो वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 13 फरवरी 2026 है, यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नई शुरूआत का गवाह बना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शास्त्रों में विजया एकादशी का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस दिन लिया गया संकल्प सदैव विजय की ओर ले जाता है। श्री मोदी ने कहा कि आज विकसित भारत के संकल्प के साथ, हम सभी सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस लक्ष्य में विजय प्राप्त करने के लिए दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ और इन नए भवनों के लिए पीएमओ टीम, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों सहित सभी को बधाई दी। उन्होंने इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियरों और श्रमिक साथियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियां साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसे भवनों से बनाई गईं। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि इन इमारतों का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीकों के रूप में किया गया था, जिनका उद्देश्य भारत को सदियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखना था।

श्री मोदी ने स्मरण किया कि कोलकाता कभी देश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान वह ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों का एक सशक्त केंद्र बन गया था। इसी कारण, 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि इसके पश्चात, औपनिवेशिक शासन की आवश्यकताओं और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का निर्माण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने इस बात पर विशेष ध्यान दिलाया कि जब रायसीना हिल्स पर इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब तत्कालीन वायसराय ने कहा था कि ये नई संरचनाएँ ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बनाई गई हैं-अर्थात, वे गुलाम भारत की धरती पर ब्रिटेन के राजा की सोच को थोपने का एक माध्यम थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रायसीना हिल्स का चयन इसलिए किया गया था ताकि ये इमारतें अन्य सभी से ऊपर रहें और कोई भी इनके बराबर खड़ा न हो सके। श्री मोदी ने इसकी तुलना सेवा तीर्थ परिसर से करते हुए कहा कि यह किसी पहाड़ी पर नहीं, बल्कि सीधे धरातल से जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि जहाँ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण औपनिवेशिक मानसिकता को लागू करने के लिए किया गया था, वहीं आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश अब भय का नहीं, विश्वास और विकास का प्रदेश है: सीएम योगी

संजना भारती संवाददाता

लखनऊ। राज्यपाल के अभिभाषण पर शुक्रवार को विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों की यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है। कर्फ्यू से कानून के राज की यात्रा है। उपद्रव से उत्सव की यात्रा है। समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों, नीतिगत बदलावों और भविष्य की दिशा का व्यापक खाका प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश अब भय का नहीं, विश्वास और विकास का प्रदेश है। अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि मानसिकता और नीतिगत प्रतिबद्धता का परिणाम है। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष की शुरूआत में राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का आधिकारिक दस्तावेज होता है। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों का सदन में आचरण अनुचित था। नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़े हुए करते हुए सीएम ने कहा कि संभवतः इसीलिए आप सदन में उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सदस्य आपके नियंत्रण से बाहर रहे होंगे। यही वह आचरण था, जिससे बिटिया घबराती थी और व्यापारी कारोबार समेटता था। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए गालिब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गालिब ने कहा था 'उम्र भर मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा।' समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की छवि अचानक खराब नहीं हुई थी, बल्कि वर्षों तक चले अव्यवस्थित आचरण और अपराध के वातावरण ने उसे प्रभावित किया था। बेटियां भयभीत थीं, व्यापारी अपना कारोबार समेटने को मजबूर थे और दंगे-कर्फ्यू आम बात थे। 2017 के बाद से प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। 2017 से पहले नीतिगत उदासीनता और प्रशासनिक शिथिलता का माहौल था, जबकि अब कानून का राज स्थापित हुआ है। 2017 के बाद से कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है।

राज्यपाल के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से 6 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। यह आंकड़ा नीति आयोग के अनुसार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबी से बाहर आने का अर्थ यह नहीं कि लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से वंचित किया जाएगा। राशन, स्वास्थ्य, आवास, पेंशन और अन्य सुविधाएं जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।

बीजेपी सरकार आमजन, गरीबों और किसान वर्ग के लिए लगातार कर रही है सराहनीय कार्य-कृष्ण बेदी

सुनीता अरड़ाना ने मंत्री कृष्ण बेदी को पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित

संजना भारती संवाददाता

असंध। नगर पालिका चेयरपर्सन सुनीता अरड़ाना के निवास पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के पहुँचने पर फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नपा चेयरपर्सन ने मंत्री को पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने नपा चेयरपर्सन सुनीता अरड़ाना की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बुजुर्गों का सम्मान भत्ता बढ़ाए जाने से हरियाणा देश का नंबर एक राज्य बन गया है। वर्तमान में लगभग 36 लाख बुजुर्गों को सम्मान भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिनकी पेंशन किसी कारणवश रुकी हुई है, उनकी जांच कर जल्द ही पुनः शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार आमजन, गरीबों और किसान वर्ग के लिए लगातार सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड, गरीबों के लिए हैप्पी कार्ड, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

भारत अमेरिका कृषि व्यापार मुद्दे के विरोध पर कैबिनेट मंत्री ने किसानों के विरोध को इंकार करते हुए कहा की बीजेपी सरकार हर फैसला किसानों के हिट में ले रही हे जिससे किसानों को फायदा मिल रहा है उन्होंने कहा की किसानों को 48 घंटे के भीतर फसल भुगतान सीधे खाते में किया जा रहा है और एमएसपी मूल्य पर फसल खरीद के अतिरिक्त किसानों को खराबे का मुआवजा देने में भी अग्रणी है।

कांग्रेस की 'हाथ' मजबूत, मल्लिकार्जुन खरगे ने जनता के विश्वास को सराहा

नई दिल्ली (एजेन्सी)। तेलंगाना के नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस बड़ी जीत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने खुशी जताते हुए इसे जनता के भरोसे की जीत बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को तेलंगाना में निकाय चुनावों में पार्टी की शानदार जीत की सराहना करते हुए कहा कि जनादेश लोगों के विश्वास को दशार्ता है। तेलंगाना में सत्तारुढ़ कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों में जोरदार जीत हासिल की। वहीं, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राज्य के 116 नगर निकायों में कुल 2,582 वार्ड में से कांग्रेस ने 1,300 से अधिक वार्ड में जीत हासिल की। बीआरएस ने लगभग 700 वार्ड और भाजपा ने लगभग 275 वार्ड में जीत दर्ज की। नगर निकाय चुनाव 11 फरवरी को हुए थे। खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तेलंगाना स्थानीय निकाय चुनावों में सराहनीय जीत के लिए कांग्रेस के प्रतिबद्ध जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मेरा आभार। यह जनादेश लोगों के विश्वास को दशार्ता है। जिन सात नगर निगमों में चुनाव हुए, उनमें से कांग्रेस ने तीन में जीत हासिल की और एक में आगे है, जबकि भाजपा ने करीमनगर और निजामाबाद में अधिकतर सीट हासिल कीं। कोठागुडेम नगर निगम में कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।

प्रदेश में हरियाणा-यूरोपीय संघ वर्किंग ग्रुप की होगी स्थापना: मुख्यमंत्री सैनी

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा भारत और यूरोपियन संघ के साथ हुए भारत-यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौते ने प्रदेश के लिए व्यापार के नए अवसर खोल दिए हैं। उन्होंने हरियाणा के उद्यमियों से इस समझौते का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा-यूरोपियन संघ वर्किंग ग्रुप की स्थापना करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री शुक्रवार को नई दिल्ली में हरियाणा यूरोपियन व्यापार संघ की बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच उभरता आर्थिक और रणनीतिक सहयोग केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है। यह हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच विश्वास, साझेदारी और साझा भविष्य का सेतु है। यह समझौता हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय है। यूरोपीय संघ के 27 देशों का यह विशाल और समृद्ध बाजार विश्व के सर्वोच्च गुणवत्ता मानकों और क्रय-शक्ति के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से अब हरियाणा और भारत के उत्पादों के लिए यूरोप के द्वार पूरी तरह खुल चुके हैं। हमारे उद्यमों, हमारे किसानों और हमारे युवाओं के लिए यह एक नया बाजार ही नहीं, बल्कि नए अवसरों का महासागर है। इसमें संभावनाओं की अनंत लहरें समाहित हैं। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम अपने सामान की गुणवत्ता पर ध्यान दें, ताकि हमारे सामान पर विश्वास जमें। इससे दुनिया भर में हमारे सामान की विश्वनीयता बढ़ेगी। भारत-ईयू समझौता से आईटी सेवाएं, डेटा विज्ञान और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में यूरोप में आपके कौशल की मांग बढ़ेगी। लाखों उच्च-स्तरीय रोजगार के अवसर आपके लिए उपलब्ध होंगे। हमारे किसान भाई-बहनों के लिए भी यह समझौता आशा की नई किरण है। अब हरियाणा के फल, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सीधे यूरोप के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे। ब्रुसेल्स, बर्लिन और पेरिस के सुपरमार्केट में जब हमारे किसानों की मेहनत दिखाई देगी। हमारे राज्य की वास्तविक शक्ति हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निहित है। यूरोपीय तकनीक और हरियाणा के कुशल श्रम मिलकर हमारी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाएगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण है। प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस को सरल बनाया है। आधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है। श्रम कानूनों में सुधार कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाया है। हमारा संदेश स्पष्ट है कि आप हमारे राज्य में आएं, निवेश करें और हम आपकी सफलता के सहभागी बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गरिमा, पारस्परिक सम्मान और विश्वास के आधार पर हम मिलकर एक बेहतर विश्व का निर्माण करेंगे।

दिल्ली सरकार का संकल्प है की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और आयुष्मान योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे-सूद

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी विधानसभा के अंतर्गत M ब्लॉक, प्रेम नगर, उत्तम नगर में नवनिर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। यह जनकपुरी में बनने वाला 5वां आरोग्य मंदिर है।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जनकपुरी के विधायक और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा की यह आरोग्य मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने की दिल्ली सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है तथा दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री सूद ने यह भी कहा की दिल्ली सरकार का लक्ष्य है की प्रत्येक नागरिक को उसके घर के निकट सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। उन्होंने कहा की 40-45 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को हर छह माह में नियमित स्वास्थ्य जांच अवश्य करानी चाहिए। निजी अस्पतालों में इस प्रकार के हेल्थ पैकेज पर लगभग 8,000 रुपए तक का खर्च आता है। यदि परिवार के चार-पांच सदस्य जांच कराएं तो सालाना खर्च 80,000 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के सभी नागरिकों को निःशुल्क जांच और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई स्तरों पर कार्य कर रही है, जिससे आम परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके। उन्होंने कहा की दिल्ली में सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयुष्मान योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा की सुविधा निःशुल्क ले सकते हैं।

पूठ कलां में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज पूठ कलां में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप केंद्र) का लोकार्पण कर इसे क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही।

लोकार्पण के उपरांत मंत्री ने आरोग्य मंदिर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने ओपीडी कक्ष, डायग्नोस्टिक सेवाओं, दवा वितरण व्यवस्था, टीकाकरण सुविधाओं तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सेवाएं सुचारु, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप संचालित हों। इस आरोग्य मंदिर के शुरू होने से पूठ कलां और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को घर के पास ही सुलभ और निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। यहां जनरल ओपीडी, आवश्यक डायग्नोस्टिक जांच, दवाइयों का वितरण, टीकाकरण, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य परामर्श और निवारक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद परिवारों को बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का नेटवर्क तेजी से मजबूत किया जा रहा है और यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से इन केंद्रों में डायग्नोस्टिक सेवाएं, वेलनेस गतिविधियां तथा समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

मंत्री ने कहा कि ऐसे उप केंद्र बड़े अस्पतालों पर दबाव कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे और लोगों को छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

सम्पादकीय

योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2027 में संभावित विधानसभा चुनावों से पूर्व 9 लाख करोड़ रु का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है। सत्तापक्ष, विशेषज्ञ और मीडिया भी इस बजट की सराहना कर रहे हैं। परंपरागत रूप से विपक्ष इसकी आलोचना करता हुए इसे योगी सरकार का अंतिम बजट कह रहा है। योगीराज के इस बजट का आकार भारत के पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट से भी कई गुना बड़ा है। यूपी में योगी बजट की एक और विशेष बात है कि किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार 10वां बजट पेश हुआ हो ऐसा पहली बार हुआ है। अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री को लगातार इतने बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। यूपी के बजट में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की छाप दिख रही है। योगी सरकार का चुनावी वर्ष के पूर्व का यह बजट प्रदेश को समस्त क्षेत्र में विकसित बनाने का आशवासन देने वाला बजट है, समाज को संतुष्टि प्रदान करने वाला बजट है। बजट में समाज के चार स्तंभों युवा, किसान, गरीब व महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में सुशिक्षित समाज, स्वस्थ समाज, नारी सशक्तीकरण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर पर्याप्त धन आबंटित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यह बजट नारी शक्ति, युवावर्ग, किसान, तथा वंचित वर्ग के उत्थान व खुशहाली को समर्पित है। यह विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाएं, उत्कृष्ट निवेश का वातावरण, नारी समृद्धि के लिए अभूतपूर्व प्रयास, युवाओं को अद्वितीय अवसर, तकनीक संग रोजगार सृजन वाला बहुआयामी बजट है। योगी सरकार प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह बजट उसका प्रमाण है। सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होने के बाद भी सरकार ने राजकोषीय अनुशासन पर बल दिया गया है और आधुनिकता पर भी ध्यान दिया गया है। सरकार लगातार बजट का आकार बड़ा करके प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए नई रणनीतियों के साथ अपनी व्यूह रचना को आगे बढ़ा रही है। महत्वपूर्ण बात है कि आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के बजट में 76 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, कृषि के लिए 20 प्रतिशत सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए विगत वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है और इस बार उनके लिए बजट में 67 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

कविता

एक कोशिश ऐसा भी

मैं अकेला खड़ा हूं अपने इस कमजोर अस्तित्व के साथ
मगर हमेशा से मैं ऐसा न था
किलकारियाँ हमारे आँगन में भी गूँजती थीं,
लोग हँसी-ठिठोली हमारे साथ भी किया करते थे।
मगर आज समय के साथ मैं पुराना हो गया हूँ।
जो कभी स्वर्णिम आभा से ढका हुआ रहता था,
आज समय के चक्र ने उसे धूल की चादर से ढक दिया है।
किसी की ज़िंदगी का भरोसा था मैं,
आज मेरी अपनी ज़िंदगी ही नहीं रही।
मैं हूँ वहीं, जहाँ मैं सालों पहले था,
तुम ही हो जो कोसों दूर निकल गए हो।
था तो मैं पहले भी वहीं, जो आज मैं हूँ,
बस आज तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही।
तुमने अपना नया बसेरा जो ढूँढ लिया है,
तुम्हें मेरे अकेलेपन का एहसास तक नहीं है।
मैं वहीं हूँ, जो तुम्हारे कदमों की आहट से झूम उठता था,
आज मैं निर्जीव-सा खड़ा हूँ तुम्हारे इंतजार में।
कभी मैं तुम्हारा बोझ ढोता था,
आज मैं स्वयं ही बोझ-सा खड़ा हूँ इस संसार में।

-अस्पर्श श्रीवास्तव, समस्तीपुर

जयंती

मोहन धारिया

जन्म: 14 फरवरी, 1925, मृत्यु: 14 अक्टूबर, 2013, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। लोकसभा और राज्यसभा के दो बार सदस्य रह चुके मोहन धारिया राष्ट्र स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय राजनीति का जाना-पहचाना नाम है। वह 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राज्य मंत्री रहे, लेकिन 1975 में आपात काल लागू होने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद वे भारतीय लोकदल में शामिल हो गए थे और 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में वाणिज्य मंत्री बने थे। मोहन धारिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे।

पुण्यतिथि

विद्यानिवास मिश्र

जन्म-28 जनवरी, 1926, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश; मृत्यु-14 फरवरी, 2005, हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार, सफल सम्पादक, संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान और जाने-माने भाषाविद थे। हिन्दी साहित्य को अपने ललित निबंधों और लोक जीवन की सुगंध से सुवासित करने वाले विद्यानिवास मिश्र ऐसे साहित्यकार थे, जिन्होंने आधुनिक विचारों को पारंपरिक सोच में खपाया था। साहित्य समीक्षकों के अनुसार संस्कृत मर्मज्ञ मिश्र जी ने हिन्दी में सदैव आँचलिक बोलियों के शब्दों को महत्व दिया। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार-"हिन्दी में यदि आँचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाये तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है, जो बेहद संस्कृतनिष्ठ है।" मिश्र जी के अभूतपूर्व योगदान के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें 'पद्मश्री' और 'पद्मभूषण' से भी सम्मानित किया था।

कल मिलेंगे

जीजा-आपके गांव की सबसे मशहूर चीज क्या है?
साली-जी मशहूर थी, उसे तो आप ले गए
जवाब सुनकर जीजा के होश उड़ गए...

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी। **मुद्रक**-देवानंद राय।
RNI No. : DELHI/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

आंदोलन, हिंसा, तख्ता पलट और बहुमत...बांग्लादेश ने डेढ़-दो साल में बहुत कुछ देख लिया

सामाजिक स्तर पर भी यह चुनाव अहम रहा। मतदान के दिन सुबह से लंबी कतारों में खड़े मतदाताओं ने यह संकेत दिया था कि लोग पारदर्शी चुनाव और स्थिर शासन चाहते हैं। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदू समाज पर हमलों की खबरों के बीच ढाका से बीएनपी के हिंदू नेता गायेश्वर चंद्र राय की जीत प्रतीकात्मक महत्व रखती है

-नीरज कुमार दुबे

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने देश के संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करके दो दशक के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी कर ली है। बीएनपी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तारिक रहमान से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। इससे पहले मोदी ने सुबह ही बीएनपी को जीत की बधाई देते हुए ट्वीट कर दिया था।

देखा जाये तो बांग्लादेश चुनाव के परिणाम से केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि संभवतः उस दौर का भी अंत हुआ है जो लंबे समय तक शेख हसीना और उनकी अवामी लीग के इर्द-गिर्द घूमता रहा। छात्र आंदोलन, आर्थिक ठहराव, भ्रष्टाचार के आरोप और फिर हिंसक टकरावों के बाद बनी राजनीतिक खाली जगह को इस चुनाव ने भरा है। इन चुनावों का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह उस उथल पुथल के बाद हुए हैं जिसने शेख हसीना की पंद्रह साल पुरानी सरकार को गिरा दिया था। छात्र आंदोलन पर सख्त कार्रवाई, बड़ी संख्या में जान हानि और उसके बाद हसीना का देश छोड़ना बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास की बड़ी घटनाएं बन चुकी हैं। अंतरिम सरकार के रूप में नोबेल सम्मान पा चुके मुहम्मद यूनुस ने देश को चुनाव तक पहुंचाया, लेकिन उनका कार्यकाल भी तमाम तरह के विवादों से भरा रहा।

चुनाव परिणामों में बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 297 सीटों में से 212 सीटें जीत कर साफ बहुमत हासिल कर लिया है। जमात ए इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 77 सीटें मिलीं, जबकि बाकी सीटें निर्दलीय और छोटे दलों के खाते में गईं। यह भी उल्लेखनीय है कि तीन दशक में पहली बार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का चुनाव चिह्न नाव मतपत्र पर नहीं था, क्योंकि पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इससे साफ है कि बांग्लादेश की राजनीति अब दो पुराने ध्रुवों की सीधी टक्कर से आगे बढ़कर नए समीकरण बना रही है।

तारिक रहमान की वापसी भी अपने आप में एक अलग राजनीतिक कथा है। कभी निर्वासन में रहे रहमान अब साठ वर्ष की उम्र में देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के तुरंत बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी और अब जीत को उनके नाम पर समर्पित करते हुए जश्न टालने की अपील की है। बीएनपी ने चुनाव परिणाम को लोकतंत्र की जीत बताया है और अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद किया है। साथ ही तारिक रहमान का 31 सूत्रीय विकास कार्यक्रम एक कल्याणकारी सरकार बनाने की बात करता है, जिससे साफ है कि वह केवल सत्ता नहीं बल्कि नीति आधारित वैधता भी चाहते हैं।

सामाजिक स्तर पर भी यह चुनाव अहम रहा। मतदान के दिन सुबह से लंबी कतारों में खड़े मतदाताओं ने यह संकेत दिया था कि लोग पारदर्शी चुनाव और स्थिर शासन चाहते हैं। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदू समाज पर हमलों की खबरों के बीच ढाका से बीएनपी के हिंदू नेता गायेश्वर चंद्र राय की जीत प्रतीकात्मक महत्व रखती है। यह नई सरकार के लिए एक संदेश भी है कि उसे अल्पसंख्यक सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने होंगे। भारत पहले ही इस मुद्दे पर चिंता जता चुका है।

अब बात भारत बांग्लादेश संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन कर तारिक रहमान को बधाई दी और दोनों देशों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साथ काम करने की बात कही। यह कदम कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने संकेत दिया है कि वह बांग्लादेश की जनता के जनादेश का सम्मान करता है और नई सरकार के साथ काम करने को तैयार है, चाहे उसका राजनीतिक झुकाव कुछ भी हो।

आने वाले दिनों में इसके कई असर दिख सकते हैं। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर संवाद जारी रह सकता है, क्योंकि यह दोनों देशों की साझा चिंता है। साथ ही व्यापार और संपर्क परियोजनाएं, जैसे सड़क, रेल और नदी मार्ग सहयोग, नई सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसलिए इन पर चर्चा जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा, अगर नई सरकार अल्पसंख्यक सुरक्षा पर भरोसा जगाती है तो द्विपक्षीय भरोसा और गहरा होगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। बीएनपी का अतीत भारत के प्रति हमेशा सहज नहीं रहा है और जमात-ए-इस्लामी जैसे दलों का प्रभाव भारत में चिंता पैदा कर सकता है। ऐसे में मोदी का शुरूआती फोन एक भरोसा बनाने वाला कदम है, जिससे नई दिल्ली यह दिखा रही है कि वह टकराव नहीं बल्कि सहयोग की राह चुनना चाहती है।

कुल मिलाकर देखें तो बांग्लादेश एक नए राजनीतिक अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जनता ने बदलाव चुना है, पर अब असली परीक्षा शासन, आर्थिक सुधार, और सामाजिक सौहार्द की है। अगर तारिक रहमान स्थिरता, समावेशन और संतुलित विदेश नीति पर ध्यान देते हैं तो यह जीत बांग्लादेश के लिए नई दिशा बन सकती है। और यदि भारत और बांग्लादेश परिपक्वता से रिश्ते आगे बढ़ाते हैं तो पूरा दक्षिण एशिया इसका लाभ देख सकता है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और निष्पक्षता का खत्म होना

इस 'संसदीय तूफान' के केन्द्र में एक ऐसा दावा है जो एक ऐसे परिकल्पित राज्य या समाज की ओर इंगित करता है जहां लोग अन्याय से पीड़ित हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला का यह सार्वजनिक दावा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की रुकावट डालने वाली चालों की वजह से प्रधानमंत्री का सदन से गैरहाजिर रहना जरूरी हो गया था, भारतीय विधायिका के इतिहास में एक अहम मोड़ है

-टी एन अशोक

भारत के संसद, जो लंबे समय से जोरदार बहस और कभी-कभी हंगामे का मैदान रहा है, अब एक ऐसे युद्ध के मैदान में बदल गया है जहां 'निष्पक्ष अंपायर' की अवधारणा ही खतरे में है। हाल ही में लगभग 120 विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास पेश करना सिर्फ एक प्रक्रिया से जुड़ी झड़प नहीं है, बल्कि यह एक ढांचागत दरार है। लोकसभा अध्यक्ष के इस दावे, जैसा पहले कभी नहीं हुआ,से शुरू हुए विवाद कि गुप्तचर सूचना से पता चला है कि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'घेरने' की योजना बना रहे थे, स्वयं में एक ऐसी घटना है जो कार्यपालिका की सुरक्षा, विधायिका के विशेषाधिकार, और संसदीय स्वतंत्रता के क्रमबद्ध तरीके से खत्म होने के खतरनाक मेल को उजागर करती है।

इस 'संसदीय तूफान' के केन्द्र में एक ऐसा दावा है जो एक ऐसे परिकल्पित राज्य या समाज की ओर इंगित करता है जहां लोग अन्याय से पीड़ित हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला का यह सार्वजनिक दावा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की रुकावट डालने वाली चालों की वजह से प्रधानमंत्री का सदन से गैरहाजिर रहना जरूरी हो गया था, भारतीय विधायिका के इतिहास में एक अहम मोड़ है। परम्परा से लोकसभा अध्यक्ष सदन के अभिभावक होते हैं, जो कार्यपालिका के दखल से सांसदों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक जरूरी बहस से प्रधानमंत्री के गैरहाजिर रहने को सही ठहराने के लिए गुप्तचर सूचना का हवाला देकर, लोकसभा अध्यक्ष ने असल में पटकथा को पलट दिया है। वह सांसदों के रक्षक से 'सरकार की ढाल' बन गए हैं। नजारा कड़वा हैः पीठासीन अधिकारी, जिसे सदन के अंदर आखिरी अधिकारी होना चाहिए, अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिचौलिए के तौर पर काम कर रहे हैं। इस कदम से पता चलता है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) और इंटेलिजेंस ब्यूरो अब स्पीकर की कुर्सी पर एक प्रॉक्सी सीट रखते हैं। अगर प्रधानमंत्री, जो देश के सबसे ताकतवर आदमी हैं, देश के सबसे सुरक्षित भवन के अंदर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों का सामना नहीं कर सकते, तो यह या तो सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी नाकामी का इशारा है या एक आसान राजनीतिक पलायन की रणनीति का।

इस विवाद को और ज्यादा जहरीला बनाया गुमनाम एप्सटीन फाइलों के वायरल होने ने, जिसमें विपक्ष के सांसदों को जोड़ा गया था, जो अजीब कपड़े फाड़ने की साजिश थी। हालांकि सरकार ने इन्हें 'एआई से बनी चालें' कहकर खारिज कर दिया, लेकिन असली नुकसान संस्थागत ताने-बाने को हुआ। जब लोकसभा अध्यक्ष की आधिकारिक बातें इंटरनेट पर टांग खींचने वाले सनसनीखेज बातों जैसी होती हैं- यह इशारा करते हुए कि महिला सांसद सुरक्षा के लिए खतरा हैं- तो सदन की इज्जत न सिर्फ. कम होती है; बल्कि वह जलकर राख हो जाती है। संसदीय विरोध को एक शारीरिक खतरे के तौर पर दिखाकर, सत्ताधारी सरकार, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के जरिए, विपक्ष के असली मतलब को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में, 'घेराव', नारे लगाना और वॉकआउट उन लोगों के हथियार हैं जिन्हें वोट नहीं दिया जाता। इन पर 'कानून व्यवस्था के जोखिम' के तौर पर छाप लगाना संसद को साफ-सुथरा बनाने और इसे एक एकल संस्कृति की गूंज वाले सदन में बदलने की एक सोची-समझी चाल है, जहां कार्यपालिका को कभी असहजता महसूस न हो। लोकसभा अध्यक्ष के कामों का तकनीकी बचाव अक्सर संविधान की चुप्पी में चला जाता है। जबकि अनुच्छेद 118 सदन को अपने नियम बनाने की इजाजत देता है, ऐसा कोई साफ प्रावधान नहीं है जो लोकसभा अध्यक्ष को 'गुप्तचर सूचना' के आधार पर प्रधानमंत्री को सत्र छोड़ने की सलाह देने का अधिकार दे। यह एक अस्पष्ट संवैधानिक 'ग्रे जोन' में आता है। हालांकि, संवैधानिक नैतिकता सिर्फ लिखी हुई बातों के बारे में नहीं है, बल्कि जो व्यवहार में किया जाता है, उसके बारे में है। लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार निष्पक्षता की सोच पर टिका होता है। जब उस सोच को पार्टी की सुविधा के लिए बदल दिया जाता है, तो यह पद अपना नैतिक वजन खो देता है। विपक्ष की शिकायत साफ है : अगर लोकसभा अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से गुप्तचर कथा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो वे रेफरी नहीं रह जाते और प्लेयर बन जाते हैं।

'कार्यपालिका से परहेज' का यह सामान्यीकरण यह पक्का करता है कि जिम्मेदारी विधायिका का मुख्य काम है, और वही सबसे पहले नुकसान में है। कुल 120 सांसदों के समर्थन वाला यह प्रस्ताव संख्या के हिसाब से मजबूत नहीं है।

भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए आराम से 272 का आंकड़ा पार कर जाएगा, इसलिए प्रस्ताव हार जाएगा, और ओम बिड़ला पद पर बने रहेंगे। तब विपक्ष को कैसे परेशानी होगी, यह सवाल खड़ा होता है। इसका जवाब 'भरोसे के बैरोमीटर' में है। यह प्रस्ताव टूटे हुए रिश्ते का एक औपचारिक रिकॉर्ड है। राहुल गांधी के हस्ताक्षर की रणनीतिगत गैरमौजूदगी भी- शायद टकराव को सीधे 'व्यक्तिगत' करने से बचने की एक चाल है- जो इस बात को नहीं छिपा सकती कि सदन का एक बड़ा हिस्सा अब अध्यक्ष को एक निष्पक्ष निर्णायक के तौर पर नहीं देखता। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास जो 1954 में जी.वी. मावलंकर से लेकर आज तक की है, एक रुझान दिखाती हैः वह यह कि ये प्रस्ताव मोशन कभी भी वोट जीतने के बारे में नहीं होते; ये विश्वास के संकट को उजागर करने के बारे में होते हैं। संसद के द्वार पर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का लोकसभा अध्यक्ष का फैसला एक 'किले जैसी विधानसभा' की छवि को और मजबूत करता है। असहमति के लिए वास्तविक जगहों को बंद करके और सांसदों के व्यवहार पर शक जताने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल करके, मौजूदा नेतृत्व भारतीय संसदीय राजनीति के डीएनए को पूरी तरह से बदल रही है। भाजपा का प्रति तर्क कि कांग्रेस ने पहले भी ऐसा ही बर्ताव किया था, अभी चल रही बढ़ती हुई बातों को नजरंदाज करता है। अगर पिछले उदाहरण गलत थे, तो इसका हल पार्टीबाजी को दोगुना करना नहीं है, बल्कि उन 'ऊंचे मानकों' को फिर से स्थापित करना है जिनकी एक उभरती हुई सुपरपावर को जरूरत है। 2026 का अविश्वास प्रस्ताव वोटों के मामले में शायद एक धीमी आवाज के साथ खत्म होगा, लेकिन इसकी गूंज बहरी कर देने वाली होगी। यह वह पल था जब दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के 'रेफरी' पर न सिर्फ एक फाउल मिस करने का आरोप लगा, बल्कि होम टीम की जर्सी पहनने का भी आरोप लगा। लोकसभा अध्यक्ष का पद सिर्फ बहुमत पर नहीं, बल्कि भरोसे पर चलता है। अगर विपक्ष को सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो एक काम करने वाली विधायिका के लिए जरूरी 'पारस्परिक भरोसे' की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। जब सदन दोबारा शुरू होता है, तो हथौड़ा अभी भी डेस्क पर लग सकता है, लेकिन उससे जो आवाज आती है वह और ज्यादा खोखली होती जाती है। भारत की संसद अब सिर्फ बहस का घर नहीं रही; यह शक का घर है, जहां कार्यपालिका की सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाता है।

खेल/विदेश/कारोबार

तारीक रहमान 2.0: बांग्लादेश में 'सत्ता परिवर्तन' और भारत-हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए इसके मायने

(एजेन्सी)।

बांग्लादेश की राजनीति में एक नए युग की शुरूआत हुई है। 17 साल के निर्वासन के बाद लंदन से लौटे तारीक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को हुए आम चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 2024 में शेख हसीना के पतन के बाद से भारत के साथ रिश्तों में आए 'शीतयुद्ध' को देखते हुए, तारीक की यह जीत दक्षिण एशिया की भू-राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

भारत के लिए तारीक रहमान का उदय एक चुनौतीपूर्ण लेकिन 'जरूरी अवसर' की तरह है। पिछले अनुभवों (2001-2006) में BNP का रुख भारत विरोधी रहा था, लेकिन इस बार 'तारीक 2.0' का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा हैः

'बांग्लादेश फर्स्ट' नीतिः ट्रंप की तर्ज पर तारीक ने 'बांग्लादेश फर्स्ट' का नारा दिया है। उन्होंने भारत, चीन और पाकिस्तान से समान दूरी बनाए रखने का वादा किया है, जो भारत के लिए मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार (जिसका झुकाव पाकिस्तान की ओर था) की तुलना में अधिक संतुलित विकल्प हो सकता है।

भारत की सक्रियताः भारत ने नतीजों की घोषणा से पहले ही तारीक को बधाई देने में जल्दबाजी दिखाई। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर का हालिया संपर्क यह दर्शाता है कि दिल्ली अब हसीना-युग की पुरानी यादों से आगे बढ़कर नए समीकरण बनाने को तैयार है।

चुनौतियांः 'जन-जेड' के बीच भारत विरोधी भावना और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग ऐसे मुद्दे हैं जो तारीक और भारत के रिश्तों की परीक्षा लेंगे।

पिछले दिसंबर में लंदन में 17 साल के देश निकाला के बाद अचानक लौटने के बाद से तारिक का रवैया कुछ पॉजिटिव रहा है। बांग्लादेश में तारिक ज़िया के नाम से मशहूर, उन्होंने 'बांग्लादेश फर्स्ट' एजेंडा का वादा किया है, जो वर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' नैरेटिव पर आधारित है। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने बांग्लादेश को भारत, चीन और पाकिस्तान जैसी क्षेत्रीय ताकतों से बराबर दूरी पर रखने का वादा किया है। मुहम्मद यूनुस के अंतरिम प्रशासन के पाकिस्तान और चीन के प्रति नरम रुख अपनाने के बाद यह भारत के लिए अच्छा संकेत है।

हालांकि, तारिक ऐसे समय में कमान संभालेंगे जब भारत के साथ रिश्ते दो समानांतर ट्रैक पर चल रहे हैं। एक तरफ, तारिक अच्छी तरह जानते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जरूरी बना रहेगा। ये देश, जो 4,000 ' का बॉर्डर शेयर करते हैं, व्यापार, बिजली और कनेक्टिविटी के जरिए करीब से जुड़े हुए हैं।

दूसरी तरफ, बांग्लादेश में, खासकर Gen-Z के बीच, लोगों का मूड भारत को लेकर शक वाला हो गया है, जब से हसीना स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत भाग गई हैं। भारत ने हसीना को वापस भेजने की बार-बार की रिक्वेस्ट पर भी टालमटोल की है। इस तरह, भारत के साथ रिश्ते सुधारना तारिक के लिए बेशक एक प्रायोरिटी होगी। भारत ने पहले ही अपनी पहुंच बढ़ा दी है। पीछे मुड़कर देखें तो, भारत ने शायद जल्दी ही इसका अंदाजा लगा लिया था। पिछले साल, जब तारिक की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही थीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने चिंता जताई और भारत का सपोर्ट ऑफर किया। BNP ने तुरंत शुक्रिया अदा करते हुए जवाब दिया।

कुछ दिनों बाद, ज़िया के गुजर जाने के बाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर 2024 की अशांति के बाद ढाका जाने वाले पहले भारतीय नेता बने और तारिक से मिले। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल लेटर भी दिया। शुक्रवार को, ढट मोदी तारिक को बधाई देने वाले पहले नेताओं में से एक थे। उन्होंने ट्वीट किया, "मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूँ।" इसने पुराने कड़वे अतीत को पीछे छोड़ते हुए सावधानी से बदलाव का माहौल बनाया (हम इस पर बाद में बात करेंगे)। भारत के लिए राहत की बात यह है कि सालों के देश निकाला के बाद ढाका लौटे तारिक रहमान ने एक बहुत अलग इमेज पेश की।

कई राज्यों के रेरा प्राधिकरण प्रकाशित नहीं कर रहे वार्षिक रिपोर्ट : एफपीसीई

(एजेन्सी)।

रियल एस्टेट डेस्क देशभर के घर खरीदारों के प्रमुख संगठन फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। संगठन का आरोप है कि अधिकांश राज्यों के रियल एस्टेट नियामक अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिससे 'रेरा' कानून का मूल उद्देश्य ही खतरे में पड़ गया है।

एफपीसीई ने एक बयान में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) की धारा 78 के उल्लंघन की तरफ इशारा किया। संगठन ने कहा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्पष्ट वैधानिक दायित्वों और बार-बार के निर्देशों के बावजूद देशभर में 75 प्रतिशत से अधिक राज्य रेरा प्राधिकरणों ने या तो कभी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है या उनका प्रकाशन बंद कर दिया है, या वे अद्यतन नहीं हैं। एफपीसीई ने मंत्रालय से सभी रेरा प्राधिकरणों को निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए नए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। संगठन ने मंत्रालय से आग्रह किया कि वह राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 82 और 83 के तहत शक्तियों का उपयोग करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहे। एफपीसीई के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा कि जब तक पुख्ता डेटा यह साबित न कर दे कि रेरा लागू होने के बाद घरों का कब्जा मिलने और कार्यप्रणाली की निष्पक्षता में बेहतरी आई है, तब तक सफलता के सभी दावे खोखले एवं बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, निर्दोष घर खरीदारों के साथ छल किया जा रहा है और इस बार इसके लिए रेरा का सहारा लिया जा रहा है। बिल्डरों के लिए यह कानून अब महज एक ऐसा प्रमाण-पत्र बन गया है, जिसकी आड़ में वे बिना किसी जवाबदेही के अपनी परियोजनाएं बेच रहे हैं।

एफपीसीई ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा ने रेरा के लागू होने के बाद से एक भी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। वहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे नौ राज्यों ने रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू किया था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया है।

न्यूयॉर्क की अदालत में निखिल गुप्ता ने स्वीकार किया अपना अपराध

(एजेन्सी)।

सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। इस मामले के मुख्य आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। संबंधित मामले के अनुसार, हत्या की कथित साजिश विफल रही थी। निखिल गुप्ता ने शुक्रवार को संबंधित आरोपों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट न्यायाधीश सारा नेटबर्न ने सिफारिश की कि जिला न्यायाधीश मैरेरो याचिका स्वीकार करें। सुनवाई की तारीख 15 मार्च तय की गई है। गुप्ता को जून 2024 में चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था और उनकी पहली पेशी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जेम्स कॉट के समक्ष मैनहट्टन संघीय अदालत में हुई थी। अदालत में पेशी के दौरान, उन्होंने पूर्व में खुद को निर्दोष बताया था। गुप्ता को चेक गणराज्य में अमेरिका सरकार के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप था। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है।

इस मामले ने भारत और अमेरिका के राजनयिक संबंधों के बीच काफी चर्चा पैदा की थी। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के शामिल होने के भी संकेत मिले थे, हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस तरह की किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक समिति गठित की है।

आईपीएल 2026 से पहले नेहल वढेरा का संकल्प, फाइनल की हार से सीखा बड़ा सबक

(एजेन्सी)।

आईपीएल 2025 के फाइनल के बाद जब पंजाब किंग्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, तब युवा बल्लेबाज नेहल वढेरा ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। 24 वर्षीय इस बल्लेबाज का यह बयान कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उनके पास लीग का ज्यादा अनुभव भी नहीं था।

फाइनल मुकाबले में वढेरा ने 18 गेंदों पर 15 रन बनाए थे। स्कोरकार्ड पर यह पारी साधारण दिखती है, लेकिन मौजूद जानकारी के अनुसार वह तब बल्लेबाजी करने आए थे जब टीम 79/3 के स्कोर पर दबाव में थी और थोड़ी ही देर में 98/4 हो गया। टीम के प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में उन्होंने मैच को अंत तक ले जाने की कोशिश की, जैसा कि कई युवा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को देखकर सीखते आए हैं, लेकिन योजना सफल नहीं हो सकी।

गौरतलब है कि उस हार के बाद वढेरा ने आत्ममंथन का रास्ता चुना। यूएई से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर वह उस अनुभव से कुछ नहीं सीखते तो वहीं के वहीं खड़े रह जाते। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया है और इस बार शब्दों से ज्यादा अपने खेल से बदलाव दिखाना चाहते हैं। उनका कहना है कि दबाव की परिस्थितियों में बेहतर निष्पादन ही किसी खिलाड़ी को भारत के लिए खेलने के स्तर तक पहुंचाता है और इस सीजन वह इसी सोच के साथ उतरेंगे।

बता दें कि पंजाब किंग्स इस बार नया सीजन शुरू होने से पहले अबू धाबी में विशेष प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। वढेरा ने बताया कि यह टीम का भारत से बाहर पहला आउटडोर कैंप है, जहां फिटनेस, डाइट, स्किल ट्रेनिंग, रिकवरी और रिहैबिलिटेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए स्टीम बाथ और आइस बाथ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे तैयारी को व्यापक रूप दिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इस समय विश्व कप के कारण व्यस्त कार्यक्रम और उत्तर भारत में ठंडे मौसम को देखते हुए अबू धाबी उपयुक्त विकल्प रहा। प्रबंधन और यूएई क्रिकेट एसोसिएशन ने टीम की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा है और अपेक्षा से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार आईपीएल 2026 का आगाज मार्च के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। ऐसे में पंजाब किंग्स के लिए यह तैयारी का चरण अहम माना जा रहा है। पिछले सीजन की निराशा को पीछे छोड़ते हुए टीम इस बार खिताब की दावेदार बनने की कोशिश में जुटी है और युवा खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी।

रूढ़ियों को तोड़ते हुए फुटबॉल में आगे बढ़ रहीं कश्मीर की लड़कियां

(एजेन्सी)।

कश्मीरी युवतियाँ अब फुटबॉल के मैदान पर अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। जुनून, मेहनत और जज्बे के साथ वे न केवल खेल में पहचान बना रही हैं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक पूर्वाग्रहों को भी चुनौती दे रही हैं। परंपरागत रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले इस खेल में ये लड़कियाँ अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। हर दिन युवा खिलाड़ी कड़ाके की ठंड और सीमित सुविधाओं के बावजूद मैदान पर जुटती हैं। कई परतों वाले गर्म कपड़े पहने होने के बाद भी उनकी फुर्ती, एकाग्रता और ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखती। वे नियमित रूप से ड्रिल, पासिंग रूटीन, शूटिंग तकनीक और स्टैमिना बढ़ाने वाले अभ्यास करती हैं। बुनियादी ढांचे की कमी और सामाजिक बाधाओं जैसी चुनौतियाँ जरूर हैं, लेकिन इनका उत्साह कम नहीं हुआ है। हर अभ्यास सत्र उनके लिए कौशल निखारने, आत्मविश्वास बढ़ाने और टीम भावना मजबूत करने का अवसर बन जाता है। डाउनटाउन क्लब के कोच इस प्रतिभा को तराशने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वह खिलाड़ियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दे रहे हैं, ताकि वे उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकें। यह क्लब अब सिर्फ अभ्यास का मैदान नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और संभावनाओं का प्रतीक बन चुका है।

इन उभरती फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और नए अवसरों की राह है। हर गोल और हर मैच के साथ कश्मीरी लड़कियाँ नई कहानी लिख रही हैं और साबित कर रही हैं कि प्रतिभा और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।

जिला कष्ट निवारण समीति की बैठक में सख्त नजर आए हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन मंत्री अनिल विज

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 15 शिकायतों की सुनवाई की। जिसमें नौ पुरानी व 6 नई शिकायतें शामिल रही।

बैठक में मंत्री अनिल विज सख्त नजर आए। उन्होंने जमीन संबंधी एक मामले की सुनवाई में आरोपी पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। साथ ही ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करने के मामले में रिश्वत मांगने की शिकायत में जेई के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश भी जारी किए। उन्होंने राजौंद नगर पालिका में पिछले साढ़े तीन साल में हुए कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की जांच विजिलेंस से भी करवाने के आदेश जारी किए। उन्होंने गांव पाई में आवास योजना के तहत कटी कालोनी में अवैध बोरवेल कनेक्शन करने के मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके जांच रिपोर्ट आगामी बैठक में देने के आदेश जारी किए। मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि यदि किसी की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक अपात्र व्यक्ति द्वारा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने पर उससे रिकवरी के भी आदेश जारी किए।

गांव तितरम निवासी संदीप मलिक व अन्य ने शिकायत दी थी कि पुलिस ने जमीन खरीदने संबंधी मामले में उनकी शिकायत पर दर्ज केस को उनकी अनुमति के बिना करनाल स्थानांतरित करके उसे रद्द करवाने व उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्री ने मामले की सुनवाई करते हुए दूसरे पक्ष में शामिल एक पुलिस कर्मचारी संदीप कुमार को जांच पूरी होने तक सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता की सुनवाई करने के आदेश दिए।

गांव किठाना निवासी कृष्ण कुमार ने सांघन में उसके रिश्तेदारों के ट्रांसफार्मर को शिफ्ट न किए जाने व इसकी एवज में जेई रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी।

■ नपा राजौंद शिकायत मामले में होगी विजिलेंस जांच, यदि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी होगी कार्रवाई: अनील विज

जिस पर सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने बिजली निगम के अधिकारियों को आदेश दिए कि शिकायतकर्ता का ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जाए और रिश्वत मांगने की शिकायत पर जेई के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।

राजौंद निवासी राकेश राणा ने शिकायत में आरोप लगाया था कि नगर पालिका राजौंद में पिछले साढ़े तीन सालों में हुए कार्यों में वित्तीय गड़बड़ी हुई है। करोड़ों रुपये के गबन की इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच हरियाणा विजिलेंस से करवाने के आदेश जारी किए। उन्होंने शिकायतकर्ता को धरना समाप्त करने के साथ-साथ उनके साथ आए एक व्यक्ति को भी जांच में शामिल करने के आदेश जारी किए। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

पाई गांव निवासी दिलबाग व अन्य ने शिकायत दी थी कि आवास योजना के तहत उन्हें जिस जमीन में प्लाट आबंटित किए गए हैं, वहां छह अवैध ट्यूबवेल कनेकशन हैं। उन्हें वहां से हटाया जाए। मंत्री ने इस मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए डीएसपी एवं गैर सरकारी सदस्य मनोज राणा को इसका सदस्य बनाते हुए निर्देश दिए कि कमेटी अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष ज्योति सैनी, विधायक सतपाल जांबा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, जिला परिषद अध्यक्ष कर्मबीर कौल, पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत, पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़, सांसद प्रतिनिधि रविंद्र धीमान, प्रशासन में डीसी अपराजिता, एसपी उपासना सहित जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्यों में रघुबीर फौजी, गोपाल सैनी, शक्ति सौदा, धीरेंद्र क्योडक, शैली मुंजाल, अरुण वर्मा, आयुष गर्ग, कपिल दीक्षित, महेंद्र चीमा, संजय सैनी के अलावा जिला प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने रमेश गोली कांड में नीतीश कुमार सहित डीएम, एसपी को सौंपा ज्ञापन

संजना भारती संवाददाता

सीवान। दैनिक अखबार के पत्रकार पर हुई गोलीबारी मामले में नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले शहर के दर्जनों पत्रकारों ने डीएम विवेक रंजन मैत्रेय एवं एसपी पूरन कुमार झा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ज्ञापन भेजा गया है। यह कदम गुरुवार रात पचरुखी थाना क्षेत्र में दैनिक अखबार के प्रखंड रिपोर्टर रमेश कुमार सिंह जसौली गांव निवासी पर हुए गोलीकांड के विरोध में उठाया गया।

घटना के अनुसार, रमेश सिंह एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे, तभी भवानी मोड़ के पास दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन पर पहले से घात लगाकर फायरिंग की। गोली उनके पेट में लग गई। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ज्ञापन में पत्रकारों ने 20 सूत्रीय मांगें रखीं, जिनमें प्रमुख रूप से रमेश सिंह पर हमला करने वाले आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग शामिल है। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा, हमलों पर सख्त कार्रवाई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। पत्रकार समुदाय ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

यह घटना बिहार में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों की ओर इशारा करती है, जहां पहले भी सीवान में राजदेव रंजन जैसी हत्याएं हो चुकी हैं। एसपी ने आश्वासन दिया है कि जांच तेज होगी और दोषियों को सजा मिलेगी।

ज्ञापन सौंपने वालों में नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, प्रमंडलीय अध्यक्ष निरंजन कुमार, जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गिरी, उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, पंकज कुमार, सचिन राज, तरुण कुमार, नितिन कुमार, राहुल, अंकेश, रिंकू, नजरे आलम सहित दर्जनों पत्रकार शामिल रहे।

कांग्रेस कमेटी की हुई बैठक, संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन के उद्देश्य से जिला अध्यक्ष (शहरी) पराग गाबा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढकर भाग लिया तथा संगठन विस्तार के साथ-साथ शहर की समस्याओं पर चर्चा की। बैठक की शुरूआत संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के एजेंडे के साथ हुई।

वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना प्राथमिकता होगी। प्रत्येक वार्ड और क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, ताकि आम जनता की समस्याओं को तुरंत उठाया जा सके। कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान तेज करने और घर-घर पहुंच बनाने का आह्वान किया गया। जिलाध्यक्ष पराग गाबा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर की कई सडकें खस्ता हालत में। आम नागरिकों, व्यापारियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी। जिसके कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अस्पताल में जल्द से जल्द आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करने की मांग की। इसके अतिरिक्त करनाल में बढ़ते क्राइम के मामलों पर भी चिंता जताई गई।

अंत में जिला अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल राजनीतिक मजबूती नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है।

उप प्रधान दिलशेर डाचर, उप प्रधान बिंदर पोसवाल, पप्पू लाठर, नाहर सिंह संधू, पंकल गाबा, ललित आहूजा, दीपक महाजन, रोहित जोशी, युवराज भट्टी, गुरमीत सिंह लाडी व सौरभ कालिया सहित अन्य मौजूद रहे।

पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सौंगल में मीडिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

■ कृष्ण प्रजापति ने विद्यार्थियों को मीडिया की भूमिका व संचार कौशल का महत्व समझाया

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सौंगल में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष मीडिया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवा मीडिया कर्मी कृष्ण प्रजापति ने छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में मीडिया का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से सूचना का प्रवाह पहले से कहीं अधिक तेज और व्यापक हो गया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया के विभिन्न प्रकारों, उसकी जिम्मेदारियों तथा समाज में उसकी सकारात्मक भूमिका को उदाहरणों सहित समझाया।

पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सौंगल में मीडिया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। (छाया: एसबी)

उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अत्यंत आवश्यक हैं। प्रभावी संवाद क्षमता न केवल शैक्षणिक जीवन में बल्कि भविष्य के करियर निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने, सही व तथ्यात्मक जानकारी साझा करने तथा सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रमेश राविश ने की। उन्होंने कहा कि ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। इस अवसर पर प्राध्यापक एवं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी मामला राम, राममेहर सिंह, सतबीर मास्टर सहित समस्त स्टाफ सदस्यों ने अतिथि का स्वागत एवं सम्मान किया।

जन शिकायतों का जल्द समाधान करें अधिकारी: डीसी अपराजिता

एसबी संवाददाता

कैथल। डीसी अपराजिता ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान शिविरों तथा अन्य पोर्टलों के माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों व समस्याओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अधिकारी समाधान शिविरों की शिकायतों को सकारात्मक दृष्टि के साथ निपटाएं तथा संबंधित नागरिक से संवाद कर उन्हें विभाग की कार्यवाही से अवगत कराकर संतुष्ट करें।

डीसी अपराजिता ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से समाधान शिविरों की लंबित शिकायतों के समाधान के लिए कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी शिकायत ज्यादा दिन तक लंबित न रहे। शिकायतों का यथासंभव उचित निपटारा किया जाये। डीसी ने कहा कि अधिकारी समाधान शिविर के अलावा सीएम विंडो की लंबित शिकायतों का भी तुरंत समाधान करवाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी शिकायत पोर्टल की शिकायतों के निपटारे की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से सीएम विंडो, एसएमजीटी, सीपीग्राम, जनसंवाद व समाधान शिविर के पोर्टल को चेक करें तथा यथाशीघ्र शिकायतों का निपटारा करें।

इस मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर एसपी उपासना, एडीसी सुशील कुमार, डीएमसी कपिल शर्मा, सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, कलायत एसडीएम अजय हुड्डा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

डीसी अपराजिता ने किया साइबर दोस्त इंटरैक्टिव ई-हैंडबुक का विमोचन

■ सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनने का दिया संदेश

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। डिजिटल युग में बढ़ती साइबर चुनौतियों और ऑनलाइन ठगी से नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। डीसी अपराजिता ने हिंदी प्राध्यापक डॉ. विजय कुमार चावला द्वारा तैयार की गई सुरक्षित डिजिटल नागरिक-साइबर दोस्त इंटरैक्टिव डिजिटल ई-हैंडबुक का विमोचन किया। उन्होंने सभी आमजन से विशेष रूप से विद्यार्थी से आह्वान किया कि वे इसमें दिए गए सुरक्षा उपायों को अपनाएं और एक जागरूक नागरिक बनें।

डीसी अपराजिता ने बताया कि डॉ. विजय कुमार ने यह ई-हैंडबुक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप तैयार की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाना है, जो तकनीक का उपयोग सकारात्मक परिवर्तन के लिए कर सकें। ई-हैंडबुक में साइबर अपराध के विभिन्न रूपों को विस्तार से समझाया गया है। इसमें फिशिंग, साइबर बुलिंग, डेटा चोरी, हैकिंग, स्मिशिंग, मैलवेयर, सोशल मीडिया अपराध, डीपफेक, ई-कॉमर्स फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग आदि के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही साइबर सुरक्षा के लिए विशेष टिप्स भी दिए गए हैं। जैसे निजी जानकारी साझा न करें, ऑनलाइन जान-पहचान वाले व्यक्तियों से न मिलें, अनजान फाइलों या ईमेल को स्वीकार न करे तथा असुरक्षित महसूस होने पर बड़ों को बताएं आदि।

साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक तुरंत 1930 पर कॉल कर सकते हैं या भारत सरकार के पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, कैथल साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर 9053052199 भी जारी किया गया है। डीसी अपराजिता ने कहा कि आज के इस डिजिटल युग में तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जहां एक ओर इंटरनेट शिक्षा और प्रगति के असीमित द्वार खोलता है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध और ऑनलाइन असुरक्षा जैसी चुनौतियाँ भी पेश करता है। इसी संदर्भ में साइबर दोस्त इंटरैक्टिव ई-हैंडबुक सभी के लिए एक अत्यंत उपयोगी है। सभी विद्यार्थी इसे जरूर पढ़ें। इसके सुरक्षा उपायों को अपनाएं और एक जागरूक व सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनें। इस मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

इस अवसर पर एसपी उपासना, एडीसी सुशील कुमार, डीएमसी कपिल शर्मा, सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, कलायत एसडीएम अजय हुड्डा, जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सम्मानित होने पर दी बधाई

एसबी संवाददाता

बछवाडा। चर्चित साहित्यकार सीताराम शेरपुरी को मुजफ्फरपुर जिले के चंदनपट्टी में बटुकदेव नारायण सम्मान से सम्मानित किया गया। बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त वरिष्ठ गीतकार राजेश कुमार सिंह के द्वारा उन्हें बटुकदेव नारायण सम्मान से नवाजा गया। सीताराम शेरपुरी की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। बताते चले कि सीताराम शेरपुरी हास्य और व्यंग्य के जाने माने कवि हैं। डॉ. विजय कपूर. डॉ. सच्चिदानंद पाठक, प्रो. हरि नारायण सिंह हरि, ज्वाला सांध्य पुष्प, मुखियाजी श्रीराम राय, प्रो. सत्यसंध भारद्वाज, कवयित्री अर्चना चौधरी अर्पण, रेखा शर्मा, रंजना लता, देवनीति राय, कवि उमेश कुंवर, सौरभ वाचस्पति, प्रवीण कुमार चुन्नू, अजय कुमार, विश्वभूषण गुप्त, अनिल झा, नितीश शेरपुरी, भोला सुरंगी आदि ने बधाई दी।

महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रभात फेरी का किया स्वागत

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असन्ध। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर नगर में पिछले 12 दिनों से श्री महादेव सेवा दल मंडल द्वारा चलाई जा रही प्रभात फेरी वार्ड नंबर 6 के समाज सेवी बाबूराम गोयल के घर पहुंची जहां पर शिव गोयल, अनिल गोयल, सुरेंद्र गोयल व दर्शन शर्मा नें शिव परिवार की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। सभी श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से स्वागत कर प्रसाद वितरित किया गया। श्री महादेव सेवा दल के प्रधान संजय भट्ट नें कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पूरे नगर में पाक्षिक प्रातः कालीन प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन श्री पातालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर की गीता कलोनी, आदर्श नगर, बाला जी कलोनी, दरबारा कॉलोनी व रामनगर सहित पूरे नगर में शिव भक्तों नें प्रभात फेरी का स्वागत कर श्रद्धा भाव से श्रद्धालुओं को जलपान कराया। उन्होंने बताया कि भोले बाबा के भजनों से पूरा नगर शिवमय हो गया।

इस अवसर पर गौसेवक सुभाष शर्मा, राकेश पटवारी, रोहित गर्ग, सुशील, नन्हा आदि उपस्थित रहे।

करनाल रिंग रोड पर सर्विस लेन की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। करनाल रिंग रोड पर सर्विस लेन की मांग को लेकर गांव सोहाना के पास किसानों का धरना लगातार जारी है। आज के धरने की अध्यक्षता किसान नेता जगमाल लाठर ने की। धरने पर बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी रही। जिन्होंने प्रशासन और एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर तीखे सवाल खड़े किए। प्रवक्ता सुरेंद्र सांगवान ने कहा कि करनाल रिंग रोड पर सर्विस लेन न होने के कारण आसपास के गांवों के किसानों, मजदूरों, दुकानदारों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेती के उपकरण, ट्रैक्टर-ट्रॉली और पैदल चलने वाले लोग हर समय दुर्घटना के खतरे में रहते हैं। कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे किसानों में गहरा रोष है।

धरने को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसानों ने गांव-गांव जाकर समर्थन जुटाने का अभियान शुरू कर दिया है। इस क्रम में आज गांव फुसगढ़, खेड़ा और छपरा का दौरा किया गया। जहां ग्रामीणों ने एकजुट होकर आंदोलन को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने कहा कि यह लड़ाई केवल किसानों की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के हक और सुरक्षा की लड़ाई है।

किसानों ने बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटे जाने के मुद्दे पर सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उत्तरी हरियाणा प्रभारी मेहताब कादियान ने कहा कि सरकार का यह फैसला बुजुर्गों के सम्मान पर सीधा हमला है और ऐसी तानाशाही सोच को भारतीय किसान यूनियन कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर सरकार ने तुरंत प्रभाव से सभी बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं की तो हरियाणा के गांव-गांव से हल्ला बोल आंदोलन की गूंज उठेगी। अब किसान और बुजुर्ग दोनों का सब्र जवाब दे चुका है। यदि जल्द बुढ़ापा पेंशन और करनाल रिंग रोड से जुड़े मुद्दों का ठोस समाधान नहीं किया गया तो भाकियू प्रदेशभर में बड़ा और निर्णायक आंदोलन छेड़ेगी। जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।

इस अवसर पर सुरेंद्र सांगवान प्रवक्ता, उत्तरी हरियाणा प्रभारी मेहताब कादियान, कार्यालय सचिव राजकुमार नौतना, किसान नेता देवेंद्र सांगवान, महिंद्र मंढाण, ईश्वर लाठर, महाबीर लाठर, वीरभान लाठर, कर्मबीर, राज सिंह, जंग बहादुर, राजबीर, जय नारायण शर्मा, दलबीर मलिक, होशियार सिंह कैरो, बलविंद्र लाठर, सज्जन लाठर, धर्मबीर सिंह सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।

भगवंत मान सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल भर का रोडमैप तैयार: हरपाल सिंह चीमा

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की सब-समिति ने आज यहां श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए साल भर के विस्तृत रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए अपनी दूसरी बैठक की। इस बैठक में इन समागमों को विश्व स्तर पर ले कर जाने और गुरू साहिब के बराबरी, मानवता एवं भक्ति के संदेश को राज्य के प्रत्येक कोने और इससे बाहर तक पहुंचाने का पक्का अहद लिया गया।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री डा. रवजोत सिंह, कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद, पर्यटन विभाग के सलाहकार दीपक बाली और विशेष इनवायटी पवन टीनूं ने महीनावार प्रोगरामों के प्रबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिससे यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि इन प्रोगरामों में आध्यात्मिक श्रद्धा, शैक्षिक प्रसार और समाज भलाई पहलकदमियों का संतुलित सुमेल हो। समागमों के आध्यात्मिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, " हमारा उद्देश्य इस ऐतिहासिक मौके को ऐसे स्तर पर मनाना है जो समाज पर श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के गहरे प्रभाव को दर्शाता है।

श्री आनंदपुर साहिब होले मुहल्ले के लिए पूरी तरह तैयार, हरजोत सिंह बैंस ने व्यापक प्रबंधों के दिए आदेश

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़/श्री आनंदपुर साहिब। होले मोहल्ले के पवित्र मौके श्री आनंदपुर साहिब में लाखों की संख्या मं; पहुंचने वाली संगत के मद्देनजर पंजाब के शिक्षा मंत्री स.हरजोत सिंह बैंस ने रूपनगर जिले के अधिकारियों को टैंट सिटी, ट्राली सिटी, समर्पित पार्किंग जोन बनाने के इलावा संगत की आसान यात्रा के लिए शटल बस और आटो-रिक्शा सेवा शुरू करने और अन्य जरुरी प्रबंध करने के निर्देश दिए है ताकि आने वाली सारी संगत के लिए आध्यात्मिक माहौल को यकीनी बनाया जा सके।

सिख परंपराओं के शानदार जशन संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए रूपनगर जिला प्रशासन के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पवित्र नगरी में लाखों की संख्या में आने वाली संगत की सुविधा प्रति वचनबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे और भारी सभा के प्रबंधन के लिए रणनीतियों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा दौरान यह यकीनी बनाया गया कि तीन दिन समागम दौरान सिख धर्म के मूल सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए।

स. बैंस ने बताया कि जिला प्रशासन को आठ एकड़ में टैंट सिटी, एक समर्पित ट्राली सिटी, 60 शटल बसें, 100 ई-रिक्शा, पैदल चलने वालों के लिए रास्ते वाली और 25 पार्किंग जोन स्थापित करने के निर्देश दिए गए है। स. हरजोत सिंह बैंस ने संबंधित सीनियर आधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि तख़्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक होने वाली संगत के लिए उचित यातायात यकीनी जाए, आस-पास को साफ-सुथरा रखा जाए और संगत को किसी भी तरह की असुविधा न होने दी जाए।

स.बैंस ने कहा, " हम मिल कर एक ऐसा माहौल सृजित करना चाहते है जहां श्रद्धा भावना पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। हम अपनी योजनाबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संगत की सुविधा के लिए आठ एकड़ में फैली टैंट सिटी से लेकर शटल बसों के बेड़े तक हर लौजिस्टिकल सहायता के लिए पुख़्ता प्रबंध किए गए है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए है कि उचित यातायात, साफ- सुथरा वातावरण यकीनी बनाया जाए और संगत को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

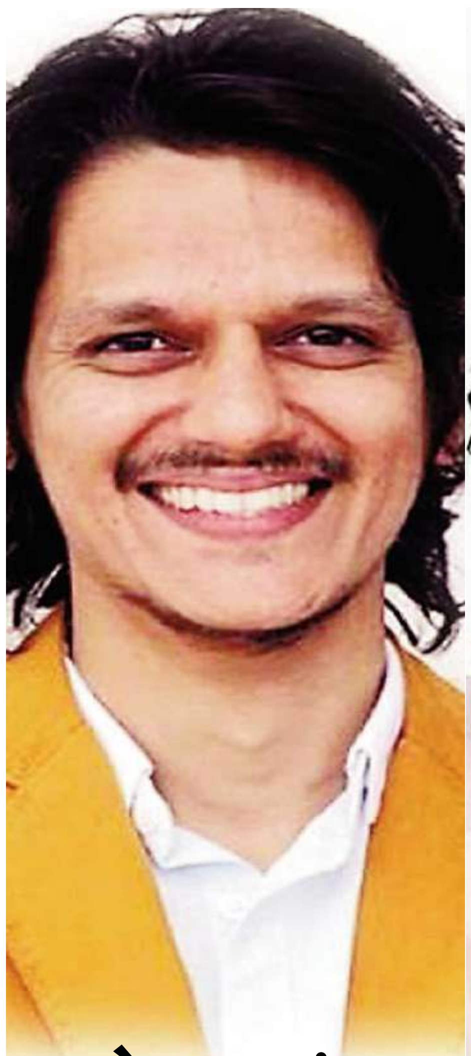

डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ काम करना मेरे लिए बहुत खास है

नेटफ्लिक्स के कार्यक्रम में वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' की स्टार कास्ट ने शिरकत की। इस दौरान अभिनेता विजय वर्मा और अनिल कपूर ने फिल्म के कलाकारों और टीम की तारीफ की। अभिनेता विजय वर्मा ने कार्यक्रम के दौरान अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत खास है। मुझे अपने फेवरेट डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला है। हंसल ने कमाल का काम किया है। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल लेटेस्ट है। इस सीरीज में मेरा किरदार बेहद शानदार है। इसमें मैंने पहली बार विक्रम के साथ काम किया है और अनिल तो एवरग्रीन है ही। हमेशा उदार, सबसे डैशिंग, सबसे शानदार और सबसे कम उम्र के एक्टर जिनके साथ मैंने काम किया। उनकी एनर्जी और काम के प्रति जोश देखकर मजा आता है। रिया और नंदीश के साथ भी पहली बार शूटिंग की और बहुत मस्ती हुई। इस प्रोजेक्ट में कई 'पहली बार' वाली चीजें हुईं। अभिनेता अनिल कपूर ने भी अपनी खुशी जाहिर की। सबसे पहले उन्होंने शो की होस्ट जॉनी लिवर की बेटी जैमी लिवर के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'जैमी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। याद है, मैंने आपको सबसे पहले कॉल किया था, जब आपने करियर भी शुरू नहीं किया था।' इसके बाद अभिनेता ने टीम की सराहना करते हुए कहा, 'यहां मौजूद सभी लोग, विजय, हंसल, विक्रम, प्रोड्यूसर, मेरा पुराना दोस्त आकाश और बाकी सभी कलाकार। आप सभी के साथ काम करके बहुत मजा आया। ये सभी युवा कलाकार मुझे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जैसा कि मैं कहता हूं, मेरा मुकाबला बढ़ रहा है। इनके साथ मुकाबला करके मैं खुद को जवान महसूस करता हूं। आप सभी युवाओं के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। '

हमें कभी पांच फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता

एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी हाल ही में 'गांधी टॉक्स' में विजय सेतुपति के अपोजिट नजर आईं। अमर उजाला से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि यह साइलेंट फिल्म उनके लिए कितनी खास थी? बातचीत के दौरान अदिति ने हिंदी फिल्मों में कम काम करने का कारण भी खुलकर बताया।

गांधी टॉक्स के लिए हामी भरने की सबसे बड़ी वजह क्या रही?

मेरा हमेशा से सपना रहा कि मैं किसी मूक फिल्म में काम करूं। जब गांधी टॉक्स मेरे पास आई, तो मैं सच में बेहद खुश हुई। फिल्म की टीम ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया। जिस तरह किशोर (निर्देशक) ने इसका ढांचा बनाया, रहमान ने शानदार संगीत दिया और विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी व सिद्धार्थ जाधव जैसे बेहतरीन कलाकार मिले। सबने मिलकर इस फिल्म को खास बना दिया। इसके अलावा मेरे किरदार को लेकर किशोर ने साफ कहा था कि यह सिर्फ एक लव इंटरेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि कहानी का भावनात्मक हिस्सा भी है।

चार साल में हमने आपको ज्यादा हिंदी फिल्मों में नहीं देखा। क्या वजह रही?

बात बस इतनी सी है कि अगर मुझे अच्छा काम मिलेगा तो ही मैं हिंदी फिल्में करूंगी। सच्चाई यह है कि हम जैसे लोग जो बाहर से बॉलीवुड में आते हैं, हमें हर फिल्म के साथ बॉलीवुड में खुद को साबित करना पड़ता है और मैं यह बिना किसी शिकायत या नकारात्मकता के कह रही हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने पांच फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हों। हमें हर नई फिल्म में खुद को फिर से प्रूव करना पड़ता है। मैं 2011 से काम कर रही हूं और मेरा मानना है कि टैलेंट अपना रास्ता खुद बना लेता है। बाकी मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे देश के कई शानदार निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला।

नीरज पांडे के साथ काम करना मेरे करियर के सबसे यादगार अनुभवों में से एक

भारतीय सिनेमा में जब किसी अभिनेता को बड़े फिल्मकारों और कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो वह अनुभव उनके करियर को बदलने वाला साबित होता है। इस कड़ी में अभिनेता अक्षय ओबेरॉय को नीरज पांडे-रितेश शाह के निर्देशन और एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला, जो उनके लिए सीखने और प्रेरणा लेने वाली यात्रा बन गई। इंटरव्यू में उन्होंने अनुभवों को साझा किया। अक्षय ओबेरॉय ने कहा, ''नीरज पांडे के साथ काम करना मेरे करियर के सबसे यादगार अनुभवों में से एक रहा है। वह जिस जॉनर में फिल्म बनाते हैं, उसमें उनकी पकड़ और समझ अनोखी है। सेट पर हर दिन उनके साथ काम करना किसी मास्टरक्लास से कम नहीं होता। उनकी सटीकता, कहानी पर पकड़ और विजुअल बनाने का तरीका मुझे लगातार सीखने का अवसर देता रहा है। मेरा मानना है कि इस फिल्म ने मुझे एक बेहतर अभिनेता बनने में मदद की है और मेरी कला को और निखारा है।'' फिल्म के निर्देशक रितेश शाह को लेकर अक्षय ने कहा, ''उनके काम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किरदारों और भावनाओं को गहराई से समझते हैं। उनके निर्देशन में हर सीन में एक वास्तविकता और वजन आता है। मैंने उनके साथ काम करते हुए हर सीन को अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली ढंग से निभाने की कला सीखी। यह अनुभव मेरे लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ बेहद संतोषजनक भी रहा।''

चिरंजीवी की अगली फिल्म में हुई अनुराग कश्यप की एंट्री

साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। इस फिल्म को न सिर्फ दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी इसकी जमकर तारीफ की है। इसी बीच चिरंजीवी की अगली फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक... ' चिरंजीवी ने अपनी अगली फिल्म फाइनल कर ली है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। खास बात यह है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप भी नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अनुराग फिल्म में एक अहम किरदार निभाएंगे। चिरंजीवी इस प्रोजेक्ट के लिए निर्देशक बॉबी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। फिल्म का शुभारंभ फरवरी में किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद शूटिंग शुरू होने की संभावना है।

'कॉकटेल 2' के बाद रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का हिस्सा होंगे शाहिद और रश्मिका

शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' में एक-साथ नजर आने वाले हैं। खबर है कि इस फिल्म के अलावा वह एक नई फिल्म में नजर आएंगे। 'कॉकटेल 2' में दोनों की केमिस्ट्री को लेकर फैंस उत्साहित हैं। अब वह अनिल शर्मा के निर्देशन में बनने वाली नई फिल्म का हिस्सा होंगे।

काम करते हुए बनी बॉन्डिंग वैरायटी इंडिया के मुताबिक 'कॉकटेल 2' में काम करते हुए उनकी काफी तारीफ हुई। इस फिल्म से उनके लिए दूसरी फिल्म का रास्ता बना। बताया जाता है कि 'कॉकटेल 2' की शूटिंग के दौरान शाहिद और रश्मिका के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई। जब उनसे नए प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया गया, तो वे एक-साथ काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। अनाम फिल्म में रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण होगा। इसे सुनील खेत्रपाल प्रोड्यूस करेंगे।

कब रिलीज होगी 'कॉकटेल 2'

फिल्म 'कॉकटेल 2' ने निर्देशक होमी अदजानिया हैं। यह 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है। इसमें शाहिद और रश्मिका के अलावा कृति सेनन भी अहम किरदार में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म इस साल सितंबर में रिलीज हो सकती है।

शाहिद और रश्मिका का काम वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहिद कपूर, विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म 'ओ रोमियो' में नजर आने वाले हैं। गैंगस्टर हुसैन उस्तरा से प्रेरित यह फिल्म 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी। वहीं, रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा के साथ 'रणबाली' में नजर आएंगी। यह फिल्म 11 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी।

मैं टीवी सीरियल टाइप का काम नहीं करना चाहता था लेकिन....

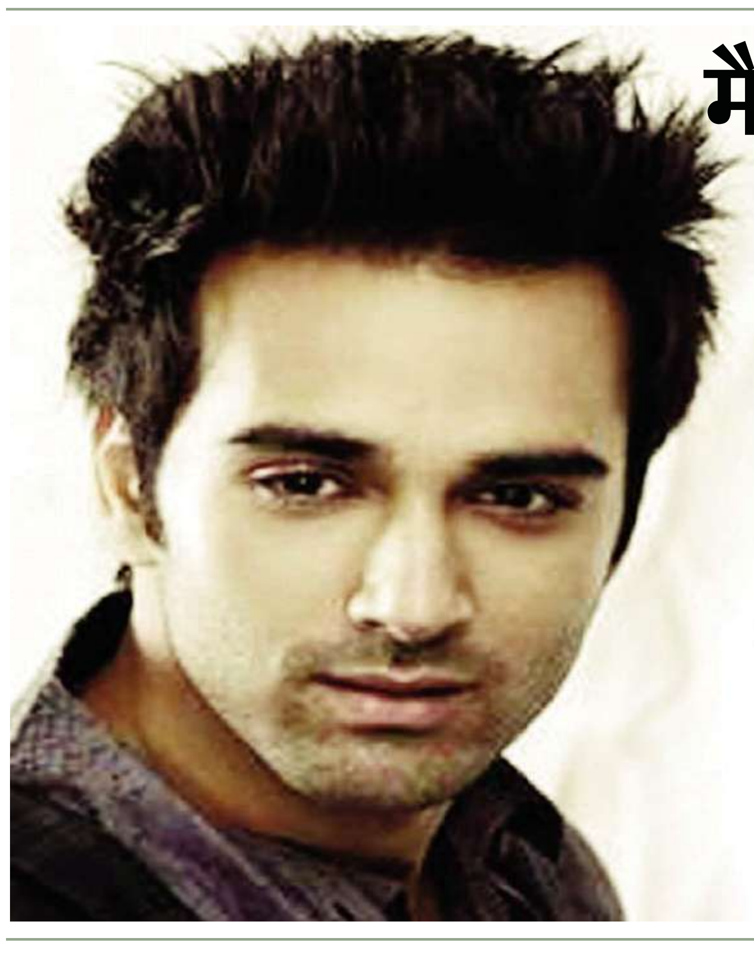

भारतीय टेलीविज़न में ओवरनाइट सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलती है और उन्हीं बेहद कम लोगों में एक नाम पुलकित सम्राट का भी शामिल है। जी हाँ, एक साधारण से टीवी ऑडिशन, जिसे उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ स्वीकार किया था, वही आगे चलकर ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, बल्कि उसी ने उन्हें हर घर का चहिता चेहरा भी बना दिया।

खुद को वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर देखनेवाले पुलकित सम्राट अपने करियर की शुरुआत टीवी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि डेली सोप्स ज़्यादातर मेलोड्रामा तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था और उसी ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। इस सिलसिले में पुलकित सम्राट कहते हैं, 'मुझे याद है मैंने साफ कहा था कि मैं टीवी सीरियल टाइप का काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं कुछ अलग और वर्सेटाइल करना चाहता था। लेकिन फिर कास्टिंग टीम ने मुझे समझाया कि यह किरदार बाकी टीवी रोल्स से अलग है। इसमें गहराई के साथ कुछ नया करने का मौका था और सबसे अहम बात यह थी कि मुझे एकता कपूर से मिलने का अवसर मिलने वाला था। इसी बात ने मुझे मुंबई आने के लिए राजी कर लिया और मैं रातों-रात दिल्ली से मुंबई आ गया।' गौरतलब है कि एकता कपूर पहले ही पुलकित की तस्वीरें देख चुकी थीं और उनसे मुलाकात के बाद वे निश्चिंत हो चुकी थी कि उनके सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के लक्ष्य वीरानी वही होंगे। ऐसे में मुंबई आते ही उनकी ग्रूमिंग शुरू हुई। उन्हें नया हेयरकट दिया गया और स्क्रीन टेस्ट कराया गया और फुटेज देखते ही उनके नाम पर मोहर लगाते हुए एकता कपूर ने कहा, 'ओके, डन। रेडी। '

हालांकि इस बड़ी सफलता के बीच भी पुलकित को रह-रहकर अपना परिवार याद आ रहा था, जिन्हें वे बिना बताए दिल्ली छोड़कर मुंबई चले आए थे। उनसे मिलने की तड़प और अपनी कामयाबी की खबर देने के लिए उन्होंने पीठ दर्द का बहाना बनाते हुए एक रात के लिए दिल्ली लौटने की इजाज़त मांगी और पहुँच गए अपने पैरेंट्स से मिलने। दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने पैरेंट्स को देखते ही वे भावुक हो उठे। उस घटना को याद करते हुए पुलकित बताते हैं, 'आंखों में आंसू लिए मैं उनके गले लगा। शब्द बहुत काम थे, बस थी तो भावनाएं। हालांकि कुछ ही घंटों बाद मैं फिर से मुंबई लौट आया लेकिन इस बार एक नए आत्मविश्वास और बदली हुई ज़िंदगी के साथ लौटा था। '

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में पुलकित की एंट्री बेहद खास रही थी। शो की जेनरेशन लीप के साथ उन्हें लॉन्च किया गया था और वे 'वो कृष्णा है' गीत के साथ सीधे दर्शकों के दिलों में उतर गए। गौर करनेवाली बात ये भी है कि यह किसी टीवी किरदार के लिए बनाए गए शुरुआती फुल-लेंथ लॉन्च सॉन्ग्स में से एक था। और इस तरह मौनी रॉय के साथ मिलकर वह नई पीढ़ी का चेहरा बने। इस सिलसिले में पुलकित कहते हैं, 'रातों-रात मैं एक जाना-पहचाना नाम बन चुका था और फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

'ग्लोरी' से ओटीटी पर कदम रखने जा रहे हैं पुलकित

'फुकरे' की लोकप्रियता के बाद 'तैश', 'सनम रे' और 'राहु केतु' में अलग-अलग तरह के किरदार निभाते हुए फिलहाल वे 'ग्लोरी' से न सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखने जा रहे हैं, बल्कि पहली बार बॉक्सर का किरदार निभाते हुए अपने करियर को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल पुलकित सम्राट की यह कहानी बताती है कि कभी-कभी एक सही मौका पूरी ज़िंदगी बदल देता है, लेकिन उस मौके को आगे ले जाने के लिए मेहनत, धैर्य और सही फैसले सबसे जरूरी होते हैं।